

राज्यपाल सचिवालय, विहार  
राजभवन, पटना-800022  
प्रेस-विज्ञप्ति

राजभवन में खादी एवं हस्तशिल्प के विकास हेतु बैठक सम्पन्न

पटना, 01 नवम्बर 2017

महामहिम राज्यपाल श्री सत्य पाल मलिक की अध्यक्षता में राजभवन सभागार में 'खादी' के विकास हेतु एक बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव श्री एस. सिद्धार्थ, उपेन्द्र महारथी शिल्प संस्थान के उपनिदेशक श्री अशोक कुमार सिन्हा, बिहार राज्य खादी बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री बी.एन. प्रसाद सहित राज्यपाल सचिवालय के वरीय अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में 'राज्यपाल सम्मेलन' (नई दिल्ली) में विचारित विषयों के आलोक में राज्य में खादी के विकास पर चर्चा हुई।

बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री मलिक ने कहा कि खादी उद्योग के विकास के लिए बुनकरों/कतिनों के समुचित प्रशिक्षण तथा उनके द्वारा उत्पादित सामग्रियों के समुचित विपणन (बाजार उपलब्ध कराने) की आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा कि इन उत्पादों की 'ऑन-लाइन बिक्री' की समुचित व्यवस्था उद्योग विभाग को करानी चाहिए, ताकि बिहार में उत्पादित खादी सामग्रियाँ तथा हस्तशिल्प की कलाकृतियाँ देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों तक पहुँच सकें। राज्यपाल ने खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं/समितियों की पुनरुद्धार-योजनाओं के तत्परतापूर्वक कार्यान्वयन पर जोर देते हुए इनके सुदृढीकरण हेतु भी ठोस प्रयास करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि बुनकरों/कारीगरों को युगीन आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी कला को परिमार्जित करना जरूरी है।

राज्यपाल ने कहा कि बिहार की मधुबनी पेंटिंग एवं भागलपुर की मंजूषा कला को वैश्विक प्रतिष्ठा प्राप्त है। उन्होंने टिकुली कला, काष्ठकला, कशीदाकारी, टेराकोटा शिल्प, सिक्की शिल्प, पेपरमैशी शिल्प, पाषाण कला, सुजनी आदि हस्तशिल्प कलाओं के विकास हेतु सरकारी एवं सांस्थिक प्रयासों को तेज करने का सुझाव दिया। उन्होंने खादी एवं हस्तशिल्प महोत्सवों एवं प्रदर्शनियों के आयोजन को भी यथासमय सम्पन्न कराते रहने को कहा। श्री मलिक ने कहा कि नेशनल एवं स्टेट हाइवे, पेट्रोल पंपों, स्टेशनों, बस-पड़ावों आदि स्थलों पर भी खादी, हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा उद्योग से जुड़ी सामग्रियों के विपणन की व्यवस्था कर खादी एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जा सकता है।

बैठक में अपने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रधान सचिव, उद्योग विभाग श्री एस. सिद्धार्थ ने राज्य में खादी के विकास की कार्य-योजना की सारगर्भित जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में 2 लाख से अधिक लोग खादी रोजगार से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि बिहार की खादी संस्थाओं को मॉडर्न चरखा (8 तकुआवाला) उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे प्रतिदिन कम-से-कम 25-30 गंडी सूत की कताई संभव हो सकेगी, फलतः कतिनों को अधिक पारिश्रमिक मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि खादी संस्थाओं को 5 चरखे पर एक लूम उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे बुनाई की क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने जानकारी दी कि वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की 'आई.डी.पी.एच. (बिहार)' योजना के तहत 16,500 शिल्पियों को लाभान्वित करने हेतु उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के लिए 30 करोड़ रु. की मंजूरी मिली है, जिसके जरिये राज्य के 6 जिलों के 15 स्थलों पर 'Common Facility Centre' बनाये जायेंगे, जहाँ शिल्पियों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होगी।

पद्मश्री श्रीमती बौआ देवी, मंजूषा ऑर्ट रिसर्च फाऊण्डेशन की उलूपी कुमारी, नेशनल एवार्डी श्री शिवन पासवान (मिथिला लोकचित्र कला) श्री विनोद कुमार मिश्र (मनीगाछी) श्री कपिलदेव (गया), शिल्पकार लाला पंडित (लालबाग, दरभंगा), श्री फिरंगी लाल गुप्ता (पाषाण शिल्प), श्री अशोक कुमार विश्वास (कैमूर) अ. राजिक रेजा (खादी ग्रामोद्योग संघ, मधुबनी), श्री आलिम अंसार (खादी ग्रामोद्योग, भागलपुर), अरूण प्रसाद (नालंदा) आदि ने भी बैठक में भाग लेकर राज्य में खादी, हस्तकरघा व हस्तशिल्प उद्योग की उपलब्धियों एवं मौजूदा चुनौतियों से महामहिम को अवगत कराया।

.....